प्राप्त दरों पर प्रमाणित क्वालिटी के बीजों की सप्लाई का एक कार्यक्रम तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किया गया है। बीज ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का एक घटक है, भी उन्नत बीज उत्पादन का आयोजन किया जाता है।

मध्य प्रदेश में सूखा

595. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके सूखाग्रस्त हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा कोष से दी गई सहायता के अलावा कितनी सहायता राशि दी है ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त धनराशि दिये जाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं और अतिरिक्त धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार राज्य के 26 जिलों में 78 तहसील, सूखे से प्रभावित हुई है, जिसके अंतर्गत 25.00 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र आता है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने आपदा राहत कोष के अलावा कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्य को नहीं दी है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने के लिए 220.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(घ) क्षति की सीमा और सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षित केन्द्रीय सहायता का आकलन करने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश को एक केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात में सूखा

595. **कु० आलिया** :

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन राज्यों ने इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सूखे की मात्रा निम्न प्रकार बतायी गई है :—

(i) **मध्य प्रदेश** :

(1)	जिलों की संख्या	26 (आंशिक रूप से)
(2)	प्रभावित जन-संख्या	107.75 लाख

(3) क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र (50 प्रतिशत से अधिक) 25.00 लाख हैक्टेयर

(ii) महाराष्ट्र :

(1) प्रभावित जिलों की संख्या 19

(2) प्रभावित गांवों की संख्या (50 प्रतिशत से अधिक) 12607

(3) प्रभावित जनसंख्या 141.47 लाख

(iii) गुजरात :

(1) प्रभावित जिलों की संख्या 16

(2) प्रभावित गांवों की संख्या लगभग 10,000

(ग) जी हां ।

(घ) केन्द्रीय दल शीघ्र ही मध्य प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगे ताकि क्षति की मात्रा तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता का जायजा लिया जा सके ।

यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के ज्ञापन और आपदा राहत निधि को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र को किसी प्रकार की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं है ।

Coconut Cultivation in Kerala

597. SHRI E. BALANANDAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether coconut cultivation is being encouraged by Government at par with other Oil Seeds ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether Government are considering a proposal for promotion and development of Coconut cultivation in Kerala during 1992-93; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) The Government of India have declared Coconut as an oilseed of tree origin and also introduced a system of declaring annual support price for copra. As Coconut is a perennial plantation crop different from other oils eeds which are annual crops, the programmes for its development and the mode of execution are also distinct.

(c) and (d) The Government of India have earmarked an outlay of Rs. 900 lakhs for promotion and development of coconut during 1992-93. This outlay consists of allocation of funds to varieus coconut growing States including Kerala. The major programmes envisaged for implementation during 1992-93 are as follows :—

1. Production and distribution of planting matrials.
2. Expansion of area under coconut.
3. Coconut Technology Development Centre for improving the post harvest processing and marketing of coconut.
4. Improving productivity of coconut in India.
5. Setting up of Publicity and Propaganda units.
6. Integrated control of major pests and diseases.
7. Surveys and evaluation schemes.
8. Infrastructure Development.

केन्द्रीय भंडार में गेहूं का स्टाक

598. श्री राघवजी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडार में गेहूं का कितना स्टाक था ;

(ख) क्या गेहूं के मल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार ने खुले बाजार में सस्ती दरों पर बिक्री करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में गेहूं जारी किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?